

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत को क्या लाभ

दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2026 को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के साथ ही 10 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के लिए भारत को ब्रिक्स का अध्यक्ष बनाया गया था, अतः भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी एवं अध्यक्षता की। ब्रिक्स के माध्यम से विश्व की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया जाता है। ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 49.5 प्रतिशत है और विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तथा वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत की भागीदारी है। इससे वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिति, दूरसंचार, कृषि, श्रम, रोजगार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, व्यापार और विश्व व्यापार संगठन सहित वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करते है। इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” रखी गई थी। शिखर सम्मेलन में 45 पन्नों एवं 140 बिंदुओं के “नई दिल्ली घोषणापत्र” को समस्त सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इस सम्मेलन में आपस में कुछ विरोधाभासी विचार रखने वाले देश (ईरान, साऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात) भी शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति एवं यूएई के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन के बीच आपस में वार्ता सम्पन्न हुई थी, जबकि दोनों देशों के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध के संदर्भ में तनाव की स्थिति कायम है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका में हुई है। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक को औपचारिक रूप दिया गया था। ब्रिक का पहिला उद्घाटन शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। वर्ष 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक को ब्रिक्स में विस्तारित करने पर सहमति हुई थी। तदनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 2024 से और इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 2025 में भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उदबोधन में उक्त ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषयों की ओर समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले कई उत्पादों के निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, इसी प्रकार चीन ने भी आवश्यक मिनरल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, इस प्रकार की स्थित पुनः न बनें इस हेतु यह सुझाव दिया गया है कि तकनीकी एवं आवश्यक मिनेरल्स को विभिन्न देशों द्वारा हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका सीधा सीधा विपरीत प्रभाव विकासशील देशों के विकास पर पड़ता है। जब हम वैश्विक स्तर पर एक परिवार की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों पर इस धरा पर निवासरत पूरी मानवजाति का समान अधिकार है। इसके उपयोग को कुछ देशों द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में तो प्रकृति को मां के समान माना जाता है, अतः प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार दोहन होना चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी आवश्यक है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के खिलाफ नहीं है केवल आवश्यकता है कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाय। हाल ही के समय में महामारी, जलवायु आपदाओं एवं सप्लाई चैन में रुकावटों ने दिखाया है कि विभिन्न देश एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। एक देश में आया संकट दूसरे देश को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स के सदस्य देशों को आपस में सहयोग बढ़ाने तथा सप्लाई चैन को मजबूती प्रदान करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच आपस में छोटे कारोबारों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें नए बाजार और पर्याप्त वित्त की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रयास भी होने चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर निर्मित हों और अंतिम पंक्ति पर खड़े नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।

व्यंग्य

प्राकृतिक तकाजों को नजरअंदाज



नेपाल की त्रासदी का संदेश है कि प्राकृतिक तकाजों को नजरअंदाज करने का समय बीत चुका है। विकास के नाम पर पर्यावरणीय सुरक्षा की बलि देना जारी रहा, तो ऐसी घटनाओं से बचना संभव नहीं रह जाएगा।

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यह चर्चा दशकों पुरानी हो चुकी है। इसके क्या घातक परिणाम होंगे, इसके लेकर वैज्ञानिक चेतावनियां भी आम चर्चा में रही हैं। कई दिन की जांच-पड़ताल के बाद अब यह साफ है कि नेपाल में 26 अगस्त को जो हुआ, वह उन चेतावनियों का ही साकार रूप लेना था। इसीलिए उस रोज हुई ग्लेशियर टूटने की घटना को महज प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्पष्टतः यह हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के हुए प्रभाव का परिणाम है। इसलिए यह एक गंभीर चेतावनी है। इसे ध्यान में रखना चाहिए कि ग्लेशियल झील के फटने से आने वाली बाढ़ जैसी त्रासदियां अनहोनी का हो जाना भर नहीं है। बल्कि ये इनसान था। यह भी गौरतलब है कि हिमालय जैसे पारिस्थिकीय नजरिए से नाजुक क्षेत्र में बिना ठोस पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए पनबिजली परियोजनाओं, सड़कों, और सुरंगों का अंधाधुंध निर्माण किया जा रहा है। इससे ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का जोखिम कई गुना बढ़ा है।

उधर बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियर टूटने से पिघलकर खतरनाक झीलों का रूप ले रहे हैं। कुल मिलाकर इस त्रासदी का संदेश है कि प्रकृति के तकाजों को नजरअंदाज करने का समय बीत चुका है। विकास के नाम पर पर्यावरणीय सुरक्षा की बलि देना और जलवायु परिवर्तन संबंधी चेतावनियों को नजरअंदाज करना जारी रहा, तो ऐसी घटनाओं से बचना अब संभव नहीं रह गया है।

प्रदेशभर में होंगे जनसेवा के कार्यक्रम

विशेष लेख: सेवा संकल्प अभियान

धनंजय राठौर

सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक महीने का देशव्यापी अभियान है। इसका मकसद मोदी के सेवा और विकास से जुड़े कामों को लोगों तक पहुंचाने के साथ जनसेवा के कार्यक्रमों को बढ़ाना है। इन कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्कूलों में प्रतियोगिताएं आदि शामिल हैं।

इस अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सांभूहिक संकल्प लेना, केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।

'सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में) निरंतर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यकाल के सम्मान में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। सेवा गतिविधियां में नागरिकों को रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसी 25 सेवा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

श्रमदान के रूप में नागरिकों से कम से कम 25 मिनट श्रमदान करने की अपील की गई है, जिसकी फोटो या वीडियो माई भारत पोर्टल पर अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलेगा।

विशेष कार्यक्रम के रूप में 17 सितम्बर 2026 को आशीर्वाद का दीया, नमो सेवा गाथा के तहत संभागीय मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर (सरगुजा), और जगदलपुर (बस्तर), के आडिटोरियम में संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर प्रस्तावित तिथि अनुसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नमो सेवा गाथा अंतर्गत नुक़ड़ नाटक, नृत्य नाटिका जिले केस्थानीय कलाकार के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा। सेवा सेतु अभियान (विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर) और सेवा फ़र्ट इन्वोेशन चैलेंज जैसी अभिनव गतिविधियां आयोजित होंगी।

इन गतिविधियों का संचालन शासकीय विभागों के साथ-साथ नागरिकों तथा

ब्लॉग

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत को क्या लाभ?

प्रह्लाद सबनानी

दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2026 को ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। ब्रिक्स का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना है। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के साथ ही 10 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हुए। वर्ष 2025-26 के लिए भारत को ब्रिक्स का अध्यक्ष बनाया गया था, अतः भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी एवं अध्यक्षता की। ब्रिक्स के माध्यम से विश्व की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया जाता है। ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 49.5 प्रतिशत है और विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तथा वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत की भागीदारी है। इससे वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स का महत्व स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य आपस में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिति, दूरसंचार, कृषि, श्रम, रोजगार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, व्यापार और विश्व व्यापार संगठन सहित वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करते है। इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम “लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण” रखी गई थी। शिखर सम्मेलन में 45 पन्नों एवं 140 बिंदुओं के “नई दिल्ली घोषणापत्र” को समस्त सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इस सम्मेलन में आपस में कुछ विरोधाभासी विचार रखने वाले देश (ईरान, साऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात) भी शामिल थे। ईरान के राष्ट्रपति एवं यूएई के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन के बीच आपस में वार्ता सम्पन्न हुई थी, जबकि दोनों देशों के बीच अमेरिका-ईरान युद्ध के संदर्भ में तनाव की स्थिति कायम है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका में हुई है। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौके पर ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक को औपचारिक रूप दिया गया था। ब्रिक का पहिला उद्घाटन शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। वर्ष 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के साथ ब्रिक्स में विस्तारित करने पर सहमति हुई थी। तदनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 2024 से और इंडोनेशिया



जनवरी 2025 में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। इसके बाद बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 2025 में भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए।

भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उदबोधन में उक्त ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषयों की ओर समस्त सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले कई उत्पादों के निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, इसी प्रकार चीन ने भी आवश्यक मिनरल के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, इस प्रकार की स्थित पुनः न बनें इस हेतु यह सुझाव दिया गया है कि तकनीकी एवं आवश्यक मिनेरल्स को विभिन्न देशों द्वारा हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका सीधा सीधा विपरीत प्रभाव विकासशील देशों के विकास पर पड़ता है। जब हम वैश्विक स्तर पर एक परिवार की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों पर इस धरा पर निवासरत पूरी मानवजाति का समान अधिकार है। इसके उपयोग को कुछ देशों द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति में तो प्रकृति को मां के समान माना जाता है, अतः प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार दोहन होना चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी आवश्यक है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के खिलाफ नहीं है केवल आवश्यकता है कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाय। हाल ही के समय में महामारी, जलवायु आपदाओं एवं सप्लाई चैन में रुकावटों ने दिखाया है कि विभिन्न देश एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। एक देश में आया संकट दूसरे देश को भी प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स के सदस्य देशों को आपस में सहयोग बढ़ाने तथा सप्लाई चैन को मजबूती प्रदान करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।



सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में सभी आयु वर्ग की महिलायें, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, स्वेच्छिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएँ, स्वयं-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं एवं आम नागरिकों को सक्रिय रूप से जोड़ा जाएगा।

यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, जबकि 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होंगे। 17 अक्टूबर 2026 को अभियान का समापन बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा।

अभियान के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच स्कूल और कॉलेजों में झाड़ंग और भाषण प्रतियोगिता सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किये गए सेवा कार्यों और विकसित भारत की संकल्पना पर जानकारी दी जाएगी और झाड़ंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, प्रदर्शनियां, सेमिनार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जागरूकता गतिविधियां होंगी। ब्लॉक स्तर पर 'सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद दी जाएगी।

25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों में 'आंगन का उत्सव आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पोषण, मातृ सहायता, टीकाकरण तथा महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी जाएगी। कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की

महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और परिवारों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

अभियान के दौरान 'कहानी बदलाव की पहल के तहत शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की वास्तविक सफलता की कहानियों को संकलन किया जाएगा। इन कहानियों के माध्यम से यह बताया जाएगा कि

सरकारी योजनाओं का प्रभाव किस तरह आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। हितग्राहियों की सफलता की कहानियां अन्य पात्र नागरिकों को भी योजनाओं का लाभ लेने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

स्कूलों में विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। 'नमो सेवा के तहत नुक़ड़ नाटक और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 'आंगन मिलन सेवा जैसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं। पिछले 25 वर्षों के सेवा कार्यों में, प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं और देश में आए बदलावों की कहानी को एक सरल, भावनात्मक और संगीतपूर्ण नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से गाँव - गाँव तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्य प्रदेशभर के स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत, सामुदायिक केंद्र एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

'विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करीब 50 ऐसे स्थान चुने जाएंगे, जिन्हें बीजेपी मोदी सरकार के दौर में हुए बदलाव का उदाहरण मानती है। इनमें गुजरात की गिफ्ट सिटी और बस्तर जैसे स्थान शामिल हैं। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी इन जगहों पर ले जाने की योजना है।

अभियान के अंतिम दिन 'जनसेवक महाकुंभ में पंचायत से संसद तक के करीब 1.25 लाख जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की योजना है। इस दौरान सामूहिक रूप से 'वदे मातरम की सभी छह कड़ियां गाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

लेखक संयुक्त संचालक, (जनसंपर्क) रायपुर हैं

कॉर्पस ₹4.90 करोड, जबकि घर की कीमत ₹4.66 करोड हो सकती है।

इस गणना में ₹40,000 का किराया 20 साल तक

आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA मिलाकर ₹25,000 या उससे कम है, तो उसे EPF के दायरे में शामिल करना कंपनी के लिए जरूरी होगा। वहीं, अगर किसी कर्मचारी की

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA ₹30,000 है और वह पहले से EPF सदस्य नहीं है, तो नई नौकरी में EPF लेना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार EPF चुन सकता है। इसलिए ₹25,000 की नई सीमा का मुख्य असर EPF कवरेज पर है, जबकि अनिवार्य योगदान की सीमा ₹15,000 ही है।

अब दूसरा व्यक्ति इसी तरह का घर ₹40,000 महीने के किराए पर लेता है। उसके पास ₹70,000 का मासिक बजट है, इसलिए किराया देने के बाद करीब ₹30,000 हर महीने निवेश करने के लिए बचते हैं।

अगर वह ₹30,000 को SIP 20 साल तक करता है और निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो यह रकम करीब ₹2.97 करोड़ हो सकती है।

ભારત ને અમેરિકા કો સિર્ફ

इस पूरे बयान में भारत ने अफ
अमेरिकी कानून के संघर्षात आर्थिक
प्रभाव का कोई अंतिम आकलन
समाजजनिक नहीं किया है। विश्व
मंत्रालय ने फिलहाल यही कहा है कि
वह आगे के घटनाक्रम पर नजर रख
रहा है। ऐसे में भारत का संदेश दो
स्तरों पर माना जा रहा है। ऊन
सुस्था जारी रहेगी और राष्ट्रीय
आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूर
कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, मीडिया
बयान में भारत ने यह साफ नहीं
किया है कि अमेरिकी कानून के
जवाब में वह कौन-से विशिष्ट कदम
उठाएगा।

इस बैठक से पहले, इस फैसले से वॉशिंगटन और फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच तनाव का एक और कारण पैदा होने की संभावना है। फिलिस्तीनी अधिकारियों और दूसरे आलोचकों का तर्क है कि अब्बास को एंटी न देने से मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल की UN की कार्यवाही में पूरी तरह से भाग लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

सरकारी टीवी चैनल 'अल-एखबारिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को हुए वोट से इस अदालत को खत्म करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया। 2012 में बनी 'काउंटर-टेरिज्म कोर्ट' का इस्तेमाल पूर्व राष्ट्रपति नशर अल-असद के शासनकाल में हजारों सिरियाई लोगों पर 'आतंकवाद से जुड़े' अपराधों के लिए मुकदमों चलाते नें किया गया था।

आतंकवाद-रोधी अदालत” बताया गया। मार्च 2025 में सीरिया के नवसंवैधानिक घोषणापत्र में साफ कहा गया था कि इस आतंकवाद अदालत के अन्यायपूर्ण फैसलों को रद्द किया जाएगा। इसमें उन लोगों की जन्त की गई संपत्ति वापस करनी की बात भी शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने 2024 में कहा था कि 2012 का वो कानून जिससे यह अदालत बनी थी, लोगों को सही न्याय नहीं दे पाता था।

ये वोट असेंबली के उन् शुरुआती बड़े विधायी फैसलों में से एक है जो उसने अपने शुरुआती सत्रों में आंतरिक नियाम और समिति बनाने के बाद लिए हैं। अल-असल परिवार का 53 साल लंबा शासन 8 दिसंबर, 2024 को खत्म हो गया। ये सब 11 दिनों के अचानक हुए हमले के बाद हुआ, जिसने सिरिया और दुनिया को चौंका दिया था। इसके साथ ही क्रूर फुलिस-राज्य का भी अंत हो गया, जो नाना और लोगों के गायब हो जाने जैसी घटनाओं के लिए जाना जाता था।

सरकार को 90 दिन का टाइम देकर मनोज जरांगे ने तौड़ा अनशन, कहा- धोखा मिला तो मुंबई पहुंचेंगे

यूपीआई चार्ज पर मोदी सरकार के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला, बताया क्यों सही है फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। जालना के अंतरवाली सराटी से मुंबई की ओर निकले मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने सरकार को तीन महीने यानी 90 दिनों का समय दिया है। उन्होंने मांग की कि तीन महीने के भीतर सातारा गजट को लागू किया जाए। मनोज जरांगे ने कहा कि वह सरकार को तीन महीने का समय दे रहे हैं। अगर सरकार ने इस दौरान धोखा दिया, तो वे मुंबई पहुंचेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज से वह अपना अनशन स्थगित कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जारी रगा।

उनसे मुलाकात के लिए सरकार का प्रतिनिधिमंडल बीड के पाटोदा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, विधायक प्रसाद लाड, विधायक सुरेश धस और बीड के जिलाधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे के साथ बातचीत की। इसके बाद आज सुबह करीब 6 बजे मनोज जरांगे और सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से चर्चा की।

मनोज जरांगे ने मुंबई पहुंच चुके करीब 1 लाख 7 हजार समर्थकों से वापस लौटने का भी आह्वान किया।



कि हजारों समर्थकों के साथ लंबी यात्रा जारी नहीं रख सकते। उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से कहा कि पाटोदा से निकलने के बाद वे उनकी गाड़ी के पीछे न आएंगे। इसके बजाय, उन्होंने उनसे सीधे खोपोलों में मिलने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर काफिला चलता रहा, तो वे यात्रा रोक सकते हैं और पाटोदा में अपना धरना फिर से शुरू कर सकते हैं या अंतरवाली सराटी लौट सकते हैं। रात करीब 1।30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बावजूद, जरांगे ने पाया कि हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को IV फ्लूइड बंद करने के बाद वे मुश्किल से ही अपने हाथ-पैर हिला पा रहे थे।

उन्होंने कहा कि फिलहाल समर्थक वापस लौटें, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर धोखा मिलने की स्थिति में आंदोलन फिर से तेज किया जाएगा।

जरांगे ने अपने अनशन के 18वें दिन भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे इतने शारीरिक रूप से थक चुके हैं

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने UPI ट्रांज़ैक्शन पर लगने वाले शुल्क के मामले में केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल-पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और चलाना सस्ता नहीं है, लेकिन साथ ही सरकार को आम ग्राहकों का ध्यान रखने की सलाह भी दी।

सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “ये शुल्क हर किसी पर नहीं लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके अलावा, आम ग्राहकों से तब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक वे एक तय सीमा से ज्यादा ट्रांज़ैक्शन न करें।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि UPI



इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और चलाना सस्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि पेमेंट सिस्टम को चलाने में काफी पैसा खर्च होता है। उन्होंने कहा, “हकीकत यह भी है कि जब कोई चीज पूरी तरह से मुफ्त में मिलती है, तो हम अक्सर उसकी सही कीमत नहीं समझते। फिर भी, भारत सरकार

को ये पक्का करना चाहिए कि आम नागरिकों पर इन शुल्कों का बोझ न पड़े। अगर कंपनियों से शुल्क लिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे भी कंपनियां UPI के जरिए काफी मुनाफा कमाती हैं।”

आने वाले विधानसभा सत्र के बारे में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री

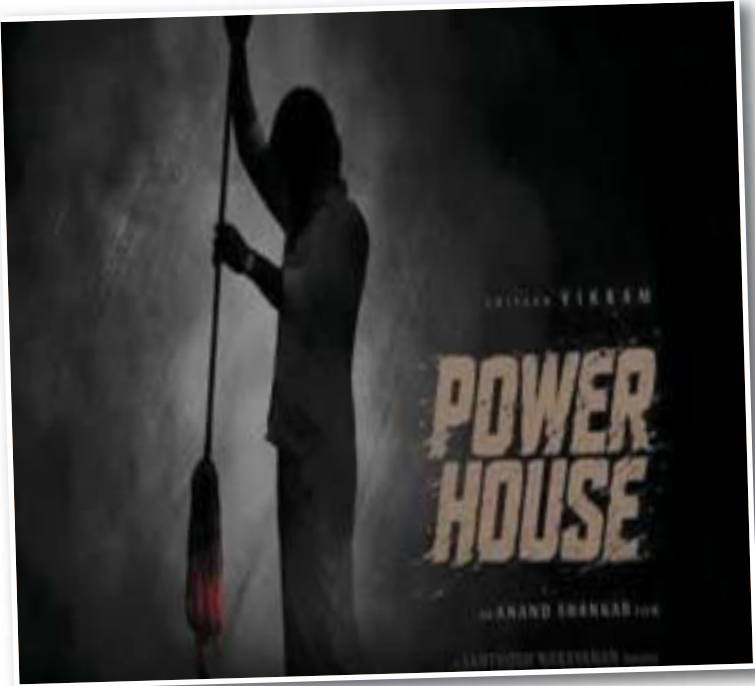
ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना होगी कि सदन का कामकाज सुचारू रूप से चले और विधायकों को संतोषजनक जवाब मिलें। उन्होंने कहा, “विधानसभा सत्र में दो तरह के एजेंडे होते हैं। एक तो सरकार का अपना विधायी कामकाज होता है। केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य की तुलना में यह स्वाभाविक रूप से कम होता है, लेकिन फिर भी ऐसे विधायी मामले होते हैं जिन्हें सरकार सदन के सामने पेश करती है। इसके साथ ही, माननीय विधायकों को चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों और लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। बिल और प्रस्ताव पेश किए जाते हैं।

विक्रम की पावर हाउस दिखने में फैमिली ड्रामा, गेट खुलते ही खून-खराबा, फैंस बोले- अपरिचित रिटर्न

अभिनेता चियान विक्रम की अगली फिल्म चियान 63 के टाइटल का एलान हो गया है। इस फिल्म का नाम पावर हाउस है। फिल्म निर्माताओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर फिल्म का टाइटल प्रोमो जारी किया , जिसमें आनंद शंकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की एक शानदार और धमाकेदार झलक दिखाई गई है।

प्रोमो में घरेलू ड्रामा, हास्य और हिंसा का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिल रहा है। साथ ही विक्रम के किरदार के एक गहरे पहलू की ओर भी इशारा किया गया है। प्रोमो की शुरुआत में अभिनेता को एक पुराने जमाने के घर में केले से भरी डाली को ले जाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद मेखा राजन, सुभाष सेल्वम और संयुक्ता हेगड़े को अपने-अपने काम पूरे करने के बाद विक्रम को रिपोर्ट करते हुए दिखाया गया है, जो एक खानपान सेवा के कारोबार की ओर इशारा करता है।

विक्रम एक ऐसे केयरटेकर की भूमिका में नजर आते हैं, जो शादियों का आयोजन करता है और अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए आत्मविश्वास से 100% गारंटी देता है। सर्वम माया फेम रिया शिबू को उनकी भतीजी के रूप में पेश किया गया है, और प्रोमो में उन्हें अक्सर अपने ही ख्यालों में खोई रहने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है।



उर्वशी और वीटीवी गणेश के साथ रसोई के एक सीन में भी हल्का-फुल्का माहौल बना रहता है, जहां वे खाना बनाते समय हंसी-मजाक करते नजर

आते हैं। हालांकि, माहौल तब बदल जाता है जब विक्रम कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम की ओर जाते हैं।

प्रोमो में विक्रम का वह रूप दिखाया गया

है जिसे अन्नियन कहा जा रहा है। गेट के खुलते ही कमरे में दो बुरी तरह घायल लोग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि विक्रम शांति से खून साफ कर रहे हैं। यह सीन बताता है कि उसके साधारण दिखने के पीछे एक रहस्यमय और निर्दयी व्यक्ति छिपा है।

पावर हाउस का प्रोमो देख अब विक्रम के फैंस तरह-तरह के कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि इस फिल्म से एक्टर का बिग कमबैक होगा। किसी ने लिखा है लगता है अपरिचित लौट रहा है। बता दें, फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी और तब पता चलेगा कि दर्शकों को विक्रम का यह अवतार कैसा लगेगा।

पावर हाउस के संगीतकार संतोष नारायणन हैं। सत्य ज्योति फिल्मस ने अपने पोस्ट में सिनेमैटोग्राफर आरडी राजशेखर, गोपी प्रसन्ना (जो प्रोडक्शन डिजाइनर भी हैं) और कॉस्ट्यूम डिजाइनर-स्टाइलिश पूर्णिमा रामस्वामी को भी टैग किया है।

सत्य ज्योति फिल्मस बैनर के तहत सेंधिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन द्वारा निर्मित पावर हाउस में शम्मी थिल्लुकन भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म से विक्रम और शंकर 10 साल बाद फिर साथ में आ रहे हैं। इस एक्टर-डायरेक्टर की जोड़ी ने साल 2016 में हिट फिल्म इरु मुगन दी थी।

8 साल बाद एक्ट्रेस की छोटे पर्दे पर वापसी, इस शो में आएंगी नजर; बताया क्यों ठुकरा रहीं थीं ऑफर्स



टीवी की मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई जल्द ही एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली हैं। जानिए किस शो में नजर आएंगी एक्ट्रेस।

एक्ट्रेस रश्मि देसाई करीब 8 साल से टीवी से दूर थीं। उन्हें पॉपुलर शो 'उतरन' से काफी पहचान मिली थी। अब इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर एक्ट्रेस छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं।

रश्मि देसाई करीब आठ साल बाद टीवी पर नजर आएंगी। रश्मि नए शो 'सयानी' में माया का किरदार निभाती दिखाई देंगी। शो में उनके साथ जाह्नवी सोनी और गौतम सिंह विग भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

टीवी पर वापसी को लेकर रश्मि ने बताया कि वह सिर्फ पर्दे पर वापस आने के लिए किसी शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। वह ऐसे किरदार और कहानी की तलाश में थीं, जिससे वह खुद को जोड़ सकें। इसी वजह से उन्होंने पिछले कुछ समय में कई ऑफर्स को ठुकरा दिया।

रश्मि ने कहा कि एक कलाकार के तौर पर उनके पास काम के कई मौके आते हैं, लेकिन सिर्फ लगातार काम करते रहना और स्क्रीन पर नजर आना ही जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक, कलाकार को ऐसा काम करना चाहिए जिसे लोग लंबे समय तक याद रखें। रश्मि को लगता है कि 'सयानी' की कहानी में वही खास बात है और इसकी कहानी कलाकारों से भी बड़ी है।

कैसा रहेगा शो में रश्मि का किरदार?

अपने किरदार माया के बारे में बात करते हुए रश्मि ने बताया कि यह सिर्फ एक काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि काफी व्यावहारिक है। अभिनेत्री के मुताबिक, हर कलाकार ऐसा किरदार निभाना चाहता है, जिसे खूबसूरती से लिखा गया हो।

कब शुरू होगा 'सयानी' शो?

रश्मि देसाई इससे पहले 'उतरन' जैसे लोकप्रिय टीवी शो में नजर आ चुकी हैं। अब करीब 8 साल बाद वह 'सयानी' के साथ टीवी पर वापसी कर रही हैं।

यह शो 23 सितंबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा।



विशाल चतुर्वेदी की भक्ति प्रधान फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार सफलता से बड़ी बजट वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। महज 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 279.80 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इसके साथ ही यह 2026 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई

करने वाली तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है। खास बात यह है कि फिल्म ने महज 10 लाख रुपये की शुरुआती कमाई के साथ अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के चलते फिल्म ने लगातार मजबूत प्रदर्शन किया और अब 300 करोड़ रुपये के वैश्विक कारोबार के बेहद करीब पहुंच गई है।

'हनुमान अंश' ने कमाई के मामले में 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'भूत बंगला' जैसी चर्चित फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इस साल अब तक केवल 'धुरंधर 2' और 'बॉर्डर 2' ही इससे अधिक कमाई करने में सफल रही हैं। फिल्म का छठा सप्ताह भी बेहद शानदार रहा। सप्ताह के आखिरी तीन दिनों में फिल्म ने 51 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया। इसके साथ भारत में इसकी कुल कमाई 222.88 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। विदेशों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिला है और वहां से करीब 16.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

बड़ी बजट वाली फिल्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 'हनुमान अंश' की कमाई लगातार जारी है। फिल्म की सफलता में दर्शकों की सकारात्मक मौखिक प्रतिक्रिया को अहम वजह माना जा रहा है। शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत की, उसने कारोबार के लिहाज से इसे 2026 की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल कर दिया है।

पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंद्रु अभिनीत 'मिर्जापुर: द मूवी' ने भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन किया है। रिलीज के 11वें दिन तक फिल्म ने भारत में करीब 225 करोड़ रुपये की सकल कमाई कर ली है। दुनिया भर में इसका कारोबार अब 275 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

फिल्म की भारत में शुद्ध कमाई 195 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। वहीं, 11वें दिन तक भारत में इसकी सकल कमाई

लगभग 225 करोड़ रुपये रही। दूसरे सप्ताह में फिल्म की कमाई की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन अब भी इसका प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है।

'मिर्जापुर: द मूवी' को अपनी लोकप्रिय फ्रैंचाइजी की पहले से स्थापित लोकप्रियता का लाभ मिल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फिल्म के हिंदी संस्करण से भारत में करीब 223 करोड़ रुपये की सकल कमाई की है, जबकि तेलुगु संस्करण से लगभग 2 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। इस तरह भारत में फिल्म की कुल सकल कमाई 225 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

फिल्म की सफलता यह भी दिखाती है कि लोकप्रिय धारावाहिक से बनी इस फ्रैंचाइजी की पकड़ केवल धारावाहिक देखने वाले दर्शकों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पर्दे पर भी इसे दर्शकों का मजबूत समर्थन मिल रहा है।

दुनियाभर में करीब 275 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 'मिर्जापुर: द मूवी' 2026 की बेहतर प्रदर्शन करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई है। भारत में इसके 250 करोड़ रुपये की सकल कमाई का आंकड़ा पार करने की संभावना बनी हुई है।

हालांकि, दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए दूसरे सप्ताह के बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार महत्वपूर्ण होगी। वहीं, 'हनुमान अंश' के 279.80 करोड़ रुपये तक पहुंचने से दोनों फिल्मों के बीच कमाई की प्रतिस्पर्धा भी दिलचस्प हो गई है।

